भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2486

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

.....

नदियों का गाद निकाला जाना

2486. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में नदियों का गाद निकालने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार दामोदर और गंगा/हुगली नदियों का गाद निकालने का विचार कर रही है या नहीं;

(ग) सरकार ने बाढ़ प्रवण पश्चिम बंगाल का गाद निकालने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में बाढ़ के पुर्वानुमान और बाढ़ के बाद पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (ग): जलोढ़ नदियों में कटाव तथा गाद का जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नदियां अपनी परिस्थितियों के प्रभाव अर्थात नदी में डिस्चार्ज, नदी का ढलान, मॉर्फोलॉजी, गाद की प्रकृति आदि के अनुसार गाद उठाती हैं, अपने साथ ले जाती हैं और गाद छोड़ती हैं। नदियों से गाद निकालने/नदियों की ड्रैजिंग का मामला लंबे समय से सरकार के विचारार्थ रहा है और इस संबंध में पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय समिति 2002 (मित्तल समिति) की राय है कि सामान्य रूप से नदियों से बड़े पैमाने पर गाद निकालना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि ड्रैजिंग सामाग्री इत्यादि के निपटान के लिए अस्थायी, अपेक्षित बड़े भू-भाग की अनुपलब्धता जैसे कई कारण होते हैं ।

संबंधित राज्यों/एजेंसियों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार नदियों की विशिष्ट पहुंच में चैनल क्षमता सुधार और नेविगेशन उद्देश्यों में ड्रैनेज रुकावट को हटाने के लिए किफायती उपायों को तैयार कर कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार, राज्यों को तकनीकी सलाह, उत्प्रेरक और उन्नयन संबंधी सहायता प्रदान करती है।

दामोदर घाटी के विनियमन के लिए दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948) के अनुसार स्थापित दामोदर घाटी निगम ने जानकारी दी है कि दामोदर नदी से गाद निकालने की कोई योजना नहीं है।

(घ): केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी) एक नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और शीघ्र बाढ़ चेतावनी जारी करने का काम सौंपा गया है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी) इस समय पश्चिम बंगाल में 16 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के एक नेटवर्क का रख-रखाव कर रहा है। इसमें से 12 लेवल पूर्वानुमान स्टेशन हैं और 4 इन-फ्लो पूर्वानुमान स्टेशन हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 2021 (नवंबर तक) कुल 488 पूर्वानुमान जारी किए गए थे। दामोदर घाटी निगम दुर्गापुर बैराज तक दामोदर घाटी जलाशय विनिमयन समिति के परामर्श से गणितीय मॉडल के आधार पर बाढ़ पूर्वानुमानों को भी जारी करता है।

प्राकृतिक आपदाओं में राहत सहायता प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होता है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय किए जाते हैं। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

****